

ओडिशा राज्य और अन्य

बनाम

गोपीनाथ दास और अन्य

9 दिसंबर, 2005

(अरिजीत पासायत और तरुण चटर्जी, जे.जे.)

प्रशासनिक कानून:

राज्य-न्यायिक समीक्षा-क्षेत्र द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय: न्यायालय राज्य की प्रशासनिक कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा या अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नहीं बैठेगा।

वर्तमान अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना उचित ठहराया था कि सशस्त्र पुलिस कर्मियों को आवर्ती आधार पर आवासों के आवंटन के मामले में राज्य द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय अवैध था।

न्यायालय ने अपील को अनुमति देते हुए अभिनिर्धारित किया-

1.1. प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय अपीलीय प्राधिकरण नहीं है और संविधान न्यायालय को नीति के मामले में कार्यपालिका को निर्देश या सलाह देने या संविधान के तहत विधानमंडल या कार्यपालिका के दायरे में आने वाले किसी भी मामले में उपदेश देने की अनुमति नहीं देता है, बशर्ते कि ये अधिकारी अपनी संवैधानिक सीमाओं या वैधानिक शक्ति का उल्लंघन न करें। न्यायिक जाँच का दायरा इस सवाल तक सीमित है कि क्या सरकार द्वारा लिया गया निर्णय किसी वैधानिक प्रावधान के खिलाफ है या यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। इस प्रकार, स्थिति यह है कि भले ही सरकार द्वारा लिया गया निर्णय न्यायालय के लिए सहमत नहीं प्रतीत होता है, वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। (701-जी-एच; 702-ए-बी)

आशिफ हामिद बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, (1989) एससी 1899 और श्री सीताराम शुगर कंपनी बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. (1990) एस.सी. 1277 पर भरोसा किया।

1.2. नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि वह अकेले यह तय कर सकती है कि विभिन्न कोणों से

सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद कौन सी नीति अपनाई जानी चाहिए। नीतिगत निर्णयों या सरकार द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के मामले में जब तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं दिखाया जाता है, अदालतों के पास हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं होगा और अदालत को समर्थन नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में कार्यपालिका के निर्णय के लिए अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं करता है। सरकार के किसी निर्णय के औचित्य का आकलन करने में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, भले ही सरकार से दूसरा दृष्टिकोण संभव हो।

मेट्रोपोलिस थिएटर कंपनी बनाम सिटी ऑफ शिकागो,
(1912) 57 एल.ईडी 730

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं.2272/1998,
ओ.जे.सी. सं. 3193/1992 में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांकित
8.8.96 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए जन कल्याण दास।

उत्तरदाताओं के लिए अरुणेश्वर गुप्ता (एन.पी.)।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

अरिजीत पासायत, जे.

इस अपील में उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि आवर्तन के आधार पर क्वार्टरों के आवंटन के मामले में राज्य द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय अवैध था।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है:

पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा उनके डी.ओ. पत्र संख्या 4322/एसएपी के माध्यम से एक नीतिगत निर्णय को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पारित किया गया था कि सभी उड़ीसा राज्य सशस्त्र पुलिस कार्मिक को कम से कम तीन साल की अवधि के लिए क्वार्टर आवंटित किए जाने थे। यह आदेश पारिवारिक आवास की कमी को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था जो प्रासंगिक समय पर उड़ीसा राज्य सशस्त्र नीति बटालियन के लिए एक गंभीर समस्या थी। यह सुनिश्चित करने के लिए भी किया गया था कि प्रत्येक पुलिस कर्मी को किराया मुक्त आवास की सुविधा का आनंद मिले और इसलिए यह बारी-बारी से किया गया था। यह प्रथा लंबे समय तक निर्बाध रूप से जारी रही।

सैन्य पुलिस प्रतिष्ठान आम तौर पर एक अलग शिविर में काम करते हैं जहां सभी कर्मियों को आवासीय आवास देने का प्रावधान किया जाता है। इसलिए, यह प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई थी कि कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के लिए आवास प्रदान किए जाएं और उस अवधि के पूरा होने के बाद उन्हें आवास खाली करने की आवश्यकता हो। इससे अन्य कर्मचारी जो आवासों से वंचित हैं, उन्हें आवास खाली करने में मदद मिलेगी। संविदात्मक समझौते- नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच तब समझौता हुआ जब उन्हें सरकारी आवास दिया गया। आदेशों की वैधता पर सवाल उठते हुए उत्तरदाताओं ने एक कीर्तन बिहारी स्वैन के साथ उड़ीसा प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया। ओ.ए. सं. 758/1989 के रूप में पंजीकृत किया गया था। आवेदन में चुनौती रोटेशन द्वारा क्वार्टरों के आवंटन की प्रणाली के लिए थी। इसके बाद, क्वार्टरों के आवंटन की प्रणाली को चुनौती देते हुए एक और आवेदन दायर किया गया था। इसे 1991 के ओ.ए. 1250 के रूप में गिना गया था। न्यायाधिकरण ने ओ.ए. संख्या 758/1989 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले पर विचार करने का उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह क्वार्टरों के

आवंटन से संबंधित एक विवाद है जो उड़ीसा सेवा संहिता (संक्षेप में 'सेवा संहिता') में प्रदान किए गए विशेष आवास नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। मूल आवेदन संख्या 1250/1991 में यह स्वीकार करने के बाद कि क्वार्टरों के आवंटन की आवर्तन प्रणाली कर्मचारियों के हित में थी, न्यायाधिकरण ने अन्य मूल आवेदन को खारिज करने के मद्देनजर आवेदन को खारिज कर दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि आवासों का आवंटन संविदात्मक आवंटन द्वारा किया गया था, इसलिए विशेष आवास नियम लागू नहीं होते हैं। इसके बाद 21 व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की जिसे 1992 के ओ.जे.सी. संख्या 6383 के रूप में पंजीकृत किया गया था। रिट याचिकाकर्ताओं में से एक पंचू साहू थे जो ओ.ए. सं. 1250/1991 में भी आवेदकों में से एक थे। ओ.ए. नं. 758/1989 को खारिज करने के बाद, न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदकों ने 1992 की ओ.जे.सी. संख्या 3193 रिट याचिका दायर की। रिट याचिका संख्या 6383/1992 को 7.7.1994 पर वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था। डिवीजन बेंच ने देखा कि चूंकि बेंच रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी, इसलिए रिट-याचिकाकर्ता याचिका को वापस लेना चाहते थे। रिट याचिका

संख्या ओ.जे.सी. 3193/1992 उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 8.8.1996 के विवादित फैसले में कहा कि आवर्ती आधार पर क्वार्टरों के आवंटन का नीतिगत निर्णय न्याय और निष्पक्षता के विपरीत और असंगत था।

अपील के समर्थन में, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है। यह ध्यान देने में विफल रहा कि सरकार के नीतिगत निर्णय में हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने नीतिगत निर्णय को रद्द करने के लिए कोई उचित कारण नहीं बताया।

उत्तरदाताओं की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है। विवादित फैसले के संचालन पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 8.5.1997 के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई थी।

प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय अपीलीय प्राधिकरण नहीं है और संविधान न्यायालय को नीति के मामले में कार्यपालिका को निर्देश देने या सलाह देने या उपदेश देने की अनुमति नहीं देता है।

कोई भी मामला जो संविधान के तहत विधानमंडल या कार्यपालिका के दायरे में आता है, बशर्ते कि ये अधिकारी अपनी संवैधानिक सीमाओं या वैधानिक शक्ति का उल्लंघन न करें।(देखें, आशिफ हामिद बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, ए.आई.आर. (1989) एस.सी. 1899, श्री सीताराम शुगर कंपनी बनाम भारत संघ (1990) एससी 1277)। न्यायिक जाँच का दायरा इस सवाल तक सीमित है कि क्या सरकार द्वारा लिया गया निर्णय किसी भी वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है या यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। इस प्रकार, स्थिति यह है कि भले ही सरकार द्वारा लिया गया निर्णय न्यायालय के लिए सहमत नहीं प्रतीत होता है, वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

उन कारणों की शुद्धता जिसने सरकार को निर्णय लेने में दूसरे के बजाय एक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया, न्यायिक समीक्षा में चिंता का विषय नहीं है और न्यायालय इस तरह की जांच के लिए उपयुक्त मंच नहीं है।

नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि वह अकेले यह अपना सकती है कि विभिन्न कोणों से सभी बिंदुओं

पर विचार करने के बाद कौन सी नीति अपनाई जानी चाहिए। नीतिगत निर्णयों या सरकार द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के मामले में जब तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं दिखाया जाता है, अदालतों के पास हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं होगा और न्यायालय को ऐसे मामलों में कार्यपालिका के निर्णय के लिए अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। सरकार के किसी निर्णय के औचित्य का आकलन करने में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, भले ही सरकार से दूसरा दृष्टिकोण संभव हो।

अदालत को लगातार खुद को याद दिलाना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने मेट्रोपोलिस थिएटर कंपनी बनाम सिटी ऑफ शिकागो, (1912) 57 एल ईडी 730 में क्या कहा था। सरकार की समस्याएं व्यावहारिक हैं और यदि उन्हें आवश्यकता नहीं है, तो खराब आवास, अतार्किक और अवैज्ञानिक हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की आलोचना भी जल्दबाजी में नहीं की जानी चाहिए। जो सबसे अच्छा है वह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है, किसी भी विकल्प के ज्ञान पर विवाद या निंदा की जा सकती

है। केवल सरकार की त्रुटियाँ हमारी न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हैं।

राहत देने के लिए उच्च न्यायालय के निष्कर्ष, जहाँ तक प्रासंगिक हैं, इस प्रकार हैं:

"4. हमने याचिकाकर्ताओं और विरोधी पक्षों की दलीलों के समर्थन में उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों को बहुत धैर्यपूर्वक सुना है। आवास की कमी संदेह या विवाद में नहीं है। क्वार्टर आवंटित करने की नीति केवल तीन वर्षों के लिए यह है कि क्या व्यावहारिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत हमें न्यायिक रूप से जांच करनी है। हम इस बात की सराहना नहीं करते हैं कि यदि क्वार्टरों की कमी है, तो आवंटन क्रमिक रूप से क्यों किया जाना चाहिए और जैसा कि उपलब्ध कराया जाएगा, पात्रता मानदंडों को ध्यान में रखते हुए और इस तरह का आवंटन उसी स्थान पर संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति की निरंतरता के बावजूद सीमित अवधि के लिए होना चाहिए। एक

व्यक्ति का स्थानांतरण किया जा सकता है, उसे तुरंत क्वार्टर खाली करने के लिए कहा जा सकता है। एक व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है और/या उसकी सेवा समाप्त हो जाती है, यह सराहना की जा सकती है कि उसे तुरंत क्वार्टर खाली कर देने चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति तैनात रहता है, तो उसकी निरंतरता के बावजूद तीन साल बाद क्वार्टर खाली करना निश्चित रूप से उचित, न्यायसंगत या तर्कसंगत नहीं है। बार-बार पूछने पर हमें कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस नीति के पीछे का अंतिम लक्ष्य क्या है ताकि असंतोष से बचा जा सके या बहुत से लोगों को खुश किया जा सके। इस तरह की नीति निष्पक्षता और न्याय की कसौटी को पूरा नहीं करती है।

5. विस्तृत कथनों को देखने और आरोपों और जवाबी आरोपों पर भी विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत वास्तविक

है। यदि याचिकाकर्ता कटक में तैनात रहते हैं और यदि उन्हें उनकी पात्रता पर विचार करने के बाद आवास प्रदान किए जाते हैं, तो उन्हें अपना आवास खाली करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, जब तक कि उनकी सेवाएं बंद नहीं हो जाती हैं या उन्हें कहीं और स्थानांतरित नहीं किया जाता है। यह रोटेशन आवंटन न्याय और निष्पक्ष खेल के विपरीत और असंगत प्रतीत होता है।"

उपर दिए गए कानूनी सिद्धांतों की पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय के निष्कर्ष रक्षात्मक नहीं लगते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए कारणों के लिए बहुत कम हैं।

इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। यदि नीतिगत निर्णय में कोई बदलाव हुआ है, तो वर्तमान निर्णय के बावजूद, यह लागू रहेगा।

अपील की अनुमति लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के दी जाती है।

डी.जी.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।